गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 169
दि. 18.10.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात में तीन साल में पूरी कैबिनेट बदली, भूपेंद्र पटेल की नई टीम में 26 मंत्री, 19 नए चेहरे और रिवाबा जडेजा सबसे युवा मंत्री

(जीएनएस)।

अहमदाबाद। गुजरात की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई कैबिनेट का गठन किया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच पर बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, साधु-संतों और बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की मौजूदगी में गुजरात की सियासत का नया चेहरा सामने आया।

तीन साल में ही पूरी कैबिनेट बदल दी गई है। भूपेंद्र पटेल सरकार की इस नई टीम में 19 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि पिछली सरकार के 10 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया।

नौ साल बाद फिर से मिला उपमुख्यमंत्री

शपथ ग्रहण समारोह का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह रहा कि गुजरात को नौ साल बाद फिर से डिप्टी सीएम मिला है। सूरत के विधायक हर्ष सांघवी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। इससे पहले गुजरात में 1973, 1994 और 2016 में उपमुख्यमंत्री का पद रहा था। अब 2025 में यह परंपरा फिर लौट आई है, जिसे सत्ता संतुलन और युवा नेतृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।

नई टीम में कौन-कौन शामिल

भूपेंद्र पटेल की नई टीम में कुल 26 मंत्री शामिल हैं — जिनमें 5 कैबिनेट

मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार और 12 राज्य मंत्री हैं।

कैबिनेट में ऋषिकेश पटेल, जीतू वघानी, कनुभाई देसाई, कुंवरजी बावलिया, नरेश पटेल, अर्जुन मोढवाडिया, प्रद्युम्न वाजा और रमन सोलंकी शामिल हैं।

स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों में ईश्वर पटेल, प्रफुल्ल पंसेरिया और मनीषा वकील को स्थान मिला है।

राज्य मंत्री के रूप में कांति अमृतिया, रमेश कटारा, दर्शनाबेन वाघेला, प्रवीण माली, त्रिकम छगा, कमलेश पटेल, संजय महिदा, पी.सी. बरंडा, स्वरूपजी ठाकोर और रिवाबा जडेजा को शामिल किया गया है।

सियासी समीकरण और संतुलन

भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है। नई टीम में तीन महिलाएं, तीन एससी, चार एसटी, नौ ओबीसी और सात पटेल समुदाय के मंत्री शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, एक ब्राह्मण, एक जैन, और एक क्षत्रिय नेता को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से उत्तर गुजरात से तीन, दक्षिण से छह और मध्य गुजरात से पांच विधायकों को मंत्री बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से आए एक नेता को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जो भाजपा के समावेशी रणनीति का संकेत देता है।

सौराष्ट्र को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व

नई कैबिनेट में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व सौराष्ट्र क्षेत्र को मिला है। यहां से कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिससे भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि 2027 के चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो गई है।

पटेल समुदाय में भी संतुलन रखने की कोशिश की गई है — चार लेउआ और तीन कडवा पाटीदारों को शामिल किया गया है।

सबसे युवा मंत्री बनीं रिवाबा जडेजा

कैबिनेट में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला नाम है रिवाबा जडेजा का — जो जामनगर उत्तर से विधायक और भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी हैं। सिर्फ 34 वर्ष की आयु में उन्हें राज्य मंत्री बनाकर भाजपा ने युवा नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण दोनों पर एक साथ दांव खेला है।

फेरबदल के पीछे पांच बड़ी वजहें

1.स्ट्रेटेजिक रीसेटः भाजपा ने सभी पुराने मंत्रियों से इस्तीफा मांगकर मुख्यमंत्री को नई टीम बनाने की पूरी स्वतंत्रता दी।

2.कमजोर प्रदर्शनः कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस उम्मीद से नीचे था, इसलिए पार्टी ने नए और ऊर्जावान चेहरों को मौका दिया।

3.जातीय समीकरणः भाजपा पटेल समुदाय और ओबीसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक आधार मजबूत करना चाहती थी।

4.लोकल बॉडी चुनावः आने वाले महीनों में होने वाले स्थानीय चुनावों को देखते हुए संगठन ने लोकप्रिय और युवा नेताओं को शामिल किया।

5.संतुलित विस्तारः राज्य की 182 सीटों के अनुपात से मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसलिए विस्तार का दायरा बढ़ाया गया।

गुजरात में यह फेरबदल सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल रिफ्रेश है। भाजपा ने इस नई कैबिनेट के जरिए यह संदेश दिया है कि पार्टी भविष्य की राजनीति को लेकर न सिर्फ तैयार है, बल्कि युवा नेतृत्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और जातीय संतुलन — तीनों पर समान रूप से ध्यान दे रही है।

ऑनलाइन जुआ-सट्टा पर सख्त निगरानी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। देश में तेजी से फैलते ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खेलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मसला है, जिस पर तत्काल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अदालत ने केंद्र से कहा कि वह दायर याचिका की प्रतिलिपि देखे और अगली सुनवाई में इस विषय पर न्यायालय की मदद करे। यह याचिका सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज (CASC) और शौर्य तिवारी की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग और रियल मनी गेम्स का बाजार तेजी से फैल रहा है। अनुमान है कि देश में करीब 65 करोड़ लोग किसी न किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या वास्तविक धन यानी पैसे के दांव वाले खेलों में शामिल होती है। रिपोर्टों के अनुसार, इस क्षेत्र का सालाना कारोबार 1.8 लाख करोड़ रुपये से भी

अधिक हो चुका है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह न सिर्फ एक आर्थिक खतरा है, बल्कि सामाजिक असंतुलन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी प्रभाव डाल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में लॉ कमीशन की 276वीं रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत में जुए को हमेशा से सामाजिक बुराई माना गया है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया था कि "अगर महाभारत के समय जुआ नियंत्रित होता, तो युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी को दांव पर नहीं लगाते।" अदालत में यह तर्क दिया गया कि यह केवल पौराणिक उदाहरण नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक चेतावनी है कि अनियंत्रित जुआ किसी भी समाज की नैतिक और पारिवारिक संरचना को ध्वस्त कर सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वयं संसद में कह चुके हैं कि "ऑनलाइन मनी गेम्स आज ड्रग्स से भी बड़ा खतरा बन चुके हैं।" मंत्रालय के अनुसार, इन एप्स के एल्गोरिद्म इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि खिलाड़ी लगभग हर बार हारता है, जिससे वह बार-बार दांव लगाकर अपने नुकसान की भरपाई की कोशिश करता रहता है और अंततः जाल में फँस जाता है। याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं — पहला, कि केंद्र सरकार का नया कानून संविधान की सातवीं अनुसूची का उल्लंघन करता है, क्योंकि जुआ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं और बेटिंग को विनियमित करने की बजाय उसे अप्रत्यक्ष रूप से वैधता प्रदान करते हैं। दूसरा, कर चोरी का विशाल जाल इस उद्योग में व्याप्त है। याचिकाकर्ताओं ने डीजीजीआई (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस) की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से जुड़ी 81,875 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी गई है। इनमें से 642 कंपनियां ऑफशोर यानी विदेशी सर्वरों पर संचालित हो रही हैं, जो भारत में कारोबार तो करती हैं लेकिन टैक्स नहीं देतीं। यह न केवल राजस्व हानि का मामला है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये सर्वर विदेशी नियंत्रण में रहते हैं।

तीसरा, याचिका में कहा गया कि फिल्मी सितारे और क्रिकेटर इन जुआ एप्स का प्रचार कर रहे हैं, जिससे युवा और बच्चे इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। विशेष रूप से अभिनेता अक्षय कुमार के बयान का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी को एक ऑनलाइन गेम के दौरान यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह उदाहरण बताता है कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म न केवल आर्थिक जाल हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अपराधों के मंच भी बनते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि "ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर" अब एक मानसिक बीमारी के रूप में दर्ज किया गया है, जो व्यक्ति के व्यवहार, नींद, पारिवारिक संबंधों और निर्णय क्षमता को गहराई से प्रभावित करती है।

अभिनेता विजय की पार्टी 'टीवीके' को अभी तक नहीं मिली चुनाव आयोग की मान्यता, करूर भगदड़ मामले पर मद्रास हाईकोर्ट में मची हलचल

(जीएनएस)।

चेन्नई। दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के सुपरस्टार और अब राजनीति में कदम रख चुके अभिनेता थलपति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम (टीवीके) इन दिनों कानूनी विवादों के केंद्र में है। शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि टीवीके अभी तक एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, इसलिए उसकी मान्यता को रद्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस खुलासे के साथ ही अदालत में लंबित उस जनहित याचिका की वैधता पर भी सवाल खड़ा हो गया, जिसमें पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग की गई थी।

दरअसल, यह मामला उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा है जो 27 सितंबर को करूर में टीवीके की एक रैली के दौरान हुआ था। रैली में उमड़ी भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। इस घटना ने तमिलनाडु की राजनीति को झकझोर कर रख दिया था। हादसे के बाद सी. सेल्वकुमार नामक व्यक्ति ने एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि टीवीके ने अपने

राजनीतिक कार्यक्रमों में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की, महिलाओं और बच्चों को भीड़ में शामिल कर उनकी जान जोखिम में डाली, इसलिए चुनाव आयोग को पार्टी की मान्यता तुरंत रद्द करनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग के वकील निरंजन राजगोपाल ने साफ कहा—"टीवीके को अब तक किसी प्रकार की औपचारिक मान्यता नहीं दी गई है। जब पार्टी मान्यता प्राप्त ही नहीं है, तो उसकी मान्यता समाप्त करने की बात निरर्थक है।" इस बयान ने अदालत में मौजूद सभी पक्षों को चौंका दिया।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि करूर भगदड़ से जुड़े सभी मामलों को प्रशासनिक दृष्टि से एक विशेष पीठ के पास भेजा जाए, ताकि एकीकृत और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इसी हादसे को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे रखे हैं, इसलिए हाईकोर्ट इस चरण में कोई अलग आदेश जारी नहीं करेगा।

याचिकाकर्ता सेल्वकुमार ने अपनी याचिका में कई व्यापक मांगें की हैं। उन्होंने आग्रह किया कि चुनाव आयोग राज्यभर में राजनीतिक रैलियों और चुनाव अभियानों में महिलाओं और बच्चों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए, और अपने 5 फरवरी 2024 के दिशा-निर्देशों को कड़ाई से लागू करे। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से लिखित रूप में वचन ले कि वे सुरक्षा मानकों और मानवाधिकारों का पालन करेंगे, और यदि कोई पार्टी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मृतकों के परिजनों को कम से कम एक करोड़ रुपये का मुआवजा और घायलों को उनकी चोटों के अनुपात में आर्थिक राहत देने की मांग की है। इस मामले की जांच वर्तमान में सीबीआई कर रही है, और प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भीड़ नियंत्रण में लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी इस त्रासदी का मुख्य कारण मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर विजय की पार्टी टीवीके ने अपने बचाव में कहा है कि यह हादसा "अचानक हुई अफरातफरी" के कारण हुआ और पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने विजय की राजनीतिक पारी की शुरुआत पर एक गहरी छाया डाल दी है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए टीवीके ने तेजी से अपना संगठन विस्तार किया था, लेकिन अब कानूनी उलझनों और विपक्षी दलों के हमलों से पार्टी की साख को झटका लग सकता है।

वर्तमान में अदालत का रुख साफ है कि जब तक टीवीके को चुनाव आयोग की औपचारिक मान्यता नहीं मिलती, तब तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई या दंडात्मक कदम उठाना संभव नहीं है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि करूर की घटना ने सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के सवालों को फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। अब तमिलनाडु की राजनीति इस बात पर टिकी है कि विजय की यह नवगठित पार्टी इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है, और क्या वह इस विवाद के बाद भी जनता के बीच अपनी साख को कायम रख पाएगी।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) पर सरकार का बड़ा कदम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण गठित

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] के खिलाफ एक और निर्णायक कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार, 17 अक्तूबर को अधिसूचना जारी कर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण (UAPA Tribunal) के गठन की घोषणा की है। इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नेल्सन सैलो करेंगे।

यह न्यायाधिकरण यह तय करेगा कि क्या एनएससीएन (के) और इसके सभी गुटों, शाखाओं तथा अग्रिम संगठनों को गैरकानूनी संघ घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं या नहीं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह कदम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5(1) के अंतर्गत उठाया गया है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना (संख्या S.O. 4709(E)) के अनुसार, यह न्यायाधिकरण केंद्र सरकार की उस अधिसूचना की समीक्षा करेगा, जिसके तहत एनएससीएन (के) को देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताकर गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। न्यायाधिकरण को यह निर्धारित करना होगा कि क्या गृह मंत्रालय के पास संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त और प्रमाणिक आधार हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले 22 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने एनएससीएन (के) को पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि यह संगठन भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है। साथ ही यह भी बताया गया कि संगठन अवैध हथियारों की तस्करी, फिरौती, धमकी और हिंसक हमलों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। एनएससीएन (के) का इतिहास पूर्वोत्तर के सबसे पुराने और खतरनाक उग्रवादी संगठनों में से एक का रहा है। यह संगठन नगालैंड के अलगाव और "ग्रेटर नागालिम" की मांग को लेकर सक्रिय है, जो म्यांमार की सीमा तक फैले भूभाग को भारत से अलग करने की कोशिश में रहा है। संगठन के संस्थापक एस. एस. खापलांग म्यांमार में रहते थे और उनकी मृत्यु के बाद भी यह गुट कई हिस्सों में विभाजित होकर सक्रिय है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना में कहा था कि एनएससीएन (के) भारत के खिलाफ हिंसक अभियान चलाने, सुरक्षाबलों पर हमले करने, और स्थानीय युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने में सक्रिय रहा है। इसके कई सदस्य और गुट विदेशी भूमि से भी आतंकी नेटवर्क संचालित करते हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा गठित यह नया न्यायाधिकरण अब पूरे मामले की कानूनी समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि क्या प्रतिबंध को बरकरार रखा जाए या हटाया जाए। यह प्रक्रिया आमतौर पर UAPA अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य होती है, ताकि किसी संगठन को बिना ठोस कारण के "गैरकानूनी" घोषित न किया जा सके। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम सरकार की "जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म" नीति को और मजबूत करता है।

लेह हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी.एस. चौहान को सौंपी गई जिम्मेदारी, सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी किए

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लेह में 24 सितंबर को हुई भीषण हिंसा की निष्पक्ष और गहराई से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ. बी.एस. चौहान को नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस जांच आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि आखिर लेह जैसे शांत और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में उस दिन ऐसा क्या हुआ जिससे स्थिति अचानक हिंसक हो गई, पुलिस को बल प्रयोग क्यों करना पड़ा और कैसे चार निर्दोष लोगों की जानें चली गईं। सरकार का कहना है कि यह जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर न तो प्रशासनिक लापरवाही छिपाई जाए और न ही किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए। 24 सितंबर की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लद्दाख के लेह क्षेत्र में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की थी। प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, परंतु देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिससे हालात बेकाबू हो गए। गोलीबारी और लाठीचार्ज में चार लोगों की मौत हो गई जबकि लगभग 90 लोग घायल हुए। इस हिंसा के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया और प्रशासन ने कर्फ्यू लगाकर हालात पर नियंत्रण पाया। घटना के दो दिन बाद, पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया, जिससे हिंसा फैली। वांगचुक की गिरफ्तारी ने लद्दाख में और आक्रोश भड़का दिया। इस घटना के बाद स्थानीय संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने केंद्र सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग की थी ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को उचित सजा दी जा सके।

अब केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी.एस. चौहान को न्यायिक जांच का दायित्व सौंपा है। चौहान देश के वरिष्ठतम न्यायविदों में गिने जाते हैं और उन्होंने कई संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष निर्णय दिए हैं। उनके नेतृत्व में गठित यह आयोग यह भी देखेगा कि क्या पुलिस की कार्रवाई उचित थी, क्या प्रशासन ने पहले से कोई निवारक कदम उठाए थे, और क्या प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने में कहीं कोई गंभीर चूक हुई।

गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार संवाद के पक्ष में है और वह एपेक्स बॉडी लेह (ABL) तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ बातचीत जारी रखेगी। मंत्रालय का कहना है कि लेह और लद्दाख के लोग भारत की सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं और मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सरकार का मानना है कि न्यायिक जांच से न केवल दोषियों की पहचान होगी बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी ठोस नीति बनाई जा सकेगी। लेह जैसे सामरिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा केवल स्थानीय समस्या नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता से जुड़ा प्रश्न है। इसीलिए केंद्र ने यह कदम बेहद सोच-समझकर उठाया है। डॉ. बी.एस. चौहान आयोग से अब यह उम्मीद की जा रही है कि वह इस पूरे प्रकरण की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाएगा। देशभर की निगाहें इस जांच पर टिकी हैं क्योंकि इससे न केवल न्याय की उम्मीद जुड़ी है बल्कि लद्दाख के भविष्य की दिशा भी तय हो सकती है।

संपादकीय

एक नायाब साल

पहली नजर में बड़े पद की चमक-दमक का अपना सम्मोहन होता है, लेकिन हकीकत में जिम्मेदारी-जवाबदेही व विपरीत चुनौतियों में सामंजस्य बैठाना कांटों का ताज पहनने जैसा ही होता है। अंतहीन जन-अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना उतना ही कठिन होता है। वैसे किसी सत्ता का एक साल बहुत लंबी अवधि नहीं होती। उसके आधार पर अंतिम मूल्यांकन करना भी जल्दबाजी ही कही जाएगी, लेकिन इससे किसी नेतृत्व या सरकार की दिशा-दशा को बोध तो हो जाता है। कमोबेश, यह कसौटी हरियाणा में एक साल पूरा कर रही नायब सैनी सरकार के लिये भी है। सामाजिक न्याय के समीकरण संतुलन की कवायद के क्रम में भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले नायब सैनी की इस पद पर ताजपोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद रही है। जब नरेंद्र मोदी चंडीगढ़-हरियाणा में संगठन का दायित्व निभा रहे थे, तो सैनी उनके कार्यालय सहयोगी थे। इस मायने में बिना राजनीतिक व समृद्ध आर्थिक पृष्ठभूमि के राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने को एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी सदाबहार मुस्कान-विनोदप्रियता के कायल रहे हैं। वे विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं को सम्मान सार्वजनिक रूप से देते नजर आते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा सत्र में मुद्दों पर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेने से भी वे नहीं चूके। वैसे तो उनके एक साल के कार्यकाल में कई चुनौतियां सामने आती-जाती रही हैं, लेकिन हाल ही में एडीजीपी वाई.पूरन कुमार व एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने सरकार के सामने असहज स्थिति व बड़ी चुनौती पेश की। हालांकि, देर से ही सही फौरी तौर पर मामले का पटाक्षेप हुआ, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुद्दे की संवेदनशीलता को महसूस कर कदम बढ़ाए। एडीजीपी द्वारा आत्महत्या की खबर उन्हें जापान दौरे के दौरान मिली तो उन्होंने दौरे में शामिल उनकी पत्नी अमनीत को अधिकारियों के साथ तुरंत भारत भेजा। भारत आते ही खुद भी वे सीधे एडीजीपी के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, तो एएसआई संदीप लाठर के घर भी परिवार को संबल देने गए।

बहरहाल, ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नायब सैनी को जरूर मिला है। कई विकास योजनाएं कायदे से सिरे चढ़ी हैं। लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना ट्रंप कार्ड साबित हुई है। विधानसभा चुनावों में इस योजना के वायदे का छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र चुनावों की तर्ज पर हरियाणा में भी भाजपा को खासा लाभ मिला। मिले परिणामों ने तमाम कयासों को निरर्थक साबित किया। हर जरूरतमंद महिला को सरकार की तरफ से 21 सौ रुपये मिलना, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन देना ही है। पहले चरण में बाइस लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। निस्संदेह, कमजोर वर्ग के लोगों के लिये अपनी छत का सपना पूरा करना एक दुष्कर कार्य है। हरियाणा सरकार ने दस हजार से अधिक आबादी वाले महाग्रामों में गरीबों को पचास-पचास गज व छोटे गांवों में सौ-सौ गज के प्लाट उपलब्ध कराये। शहरों में ये 25 गज के रहे। वहीं प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत मिलने वाले ढाई-ढाई लाख रुपये ने उनके घर के सपने को हकीकत बनाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी की खासियत लोगों के साथ सहज उपलब्धता है। उनकी सुबह कबीर कुटीर में जन संवाद से शुरू होती है और रात फाइलों के साथ खत्म होती है। जनता के लिये सहज उपलब्धता और निरंतर संवाद लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त होती है। उनके चंडीगढ़ आवास में सुबह से ही मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। निस्संदेह, आम जन ही सरकार को बेहतर फीडबैक दे सकते हैं, जो नौकरशाही की जटिलताओं के चलते सहज अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। बेरोजगारी की समस्या किसी भी सरकार के लिये बड़ी चुनौती होती है। राज्य में चौबीस हजार बेरोजगारों को ग्रुप सी की नौकरियां देना राज्य सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा गया। वहीं लोकसेवा आयोग के माध्यम से 1311 पदों पर चयन और एचकेआरएन पोर्टल को पारदर्शी भर्ती प्रणाली के रूप में विकसित करना, राज्य सरकार की रोजगार के साथ स्थायित्व की नीति का संकेत माना जा सकता है। विश्वास किया जाना चाहिए कि नायब सरकार आने वाले चार सालों में जनाकांक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतर पाएगी।

वैश्विक चुनौतियों के बीच अंदरूनी मुद्दों पर ध्यान जरूरी

> तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां बढ़ी हैं। इनमें मध्य पूर्व के कुछ देशों व अमेरिका से संबंधों में बदलाव प्रमुख हैं। पाकिस्तान से मई झड़प के बाद दोनों ओर से तल्ख बयानबाजी और धमकियां जारी हैं। लेकिन देश के सीमावर्ती राज्यों में तनाव ज्यादा चिंताजनक है। वहां मूल समस्याओं का हल जरूरी है।

भू-राजनीतिक सत्ता के खेल के पहलू सामान्य से कहीं ज़्यादा तेजी से चल रहे हैं, और मैं खुद को हम पर पड़ने वाले प्रभाव पर आत्मचिंतन करता पा रहा हूं। हमास-इस्राइल संघर्ष मामले में शुरुआत हो चुकी है, और युद्धविराम हो गया है; इस्राइली बंधकों और फ़लस्तीनी कैदियों की अदला-बदली हुई है। इस लड़ाई से अमेरिका, ब्रिटेन, इस्राइल, मिस्र, लेबनान, यमन, ईरान, कतर, सीरिया के अलावा कुछ अन्य देश भी जुड़े थे, हो सकता है जिन्हें मैं नज़रअंदाज़ कर गया। शांति सदा स्वागत योग्य है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह स्थायी हो पाएगी। सही तरह अमेरिका की मदद प्राप्त इस्राइल ने इस लड़ाई में अपना वर्चस्व स्पष्टतया प्रदर्शित किया है। यह भी दिखाया कि इस्राइल की अति-दक्षिणपंथी विचारधारा में फ़लस्तीनी राज्य के विचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, और फिलहाल यही नीति हावी है। यह गाज़ा पर बमबारी, वैस्ट बैंक पर बसने वालों को दिए समर्थन और तमाम विरोध कठोरता से कुचलने में देखने को मिला। क्या इससे फ़लस्तीनी देश और द्वि-राष्ट्र समाधान की मांग समाप्त हो जाएगी...शायद नहीं।

अंततः, यह तीन प्राचीन समुदायों और धर्मों के बीच की सांप्रदायिक रार है। यरुशलम को लेकर सदियों से लड़ाई जारी है... यहीं से ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई, और यह मान बैठना ज्यादा ही सरल होगा कि अब सब झगड़ा सुलझ गया है। मध्य पूर्व के विशाल कच्चे तेल भंडारों पर नियंत्रण की इच्छा भी महाशक्तियों के लिए हस्तक्षेप करने में बड़ा लालच है। यह देखते हुए कि यूरोप के अधिकांश देशों और ब्रिटेन ने हाल ही में फ़लस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, हमास को निरस्त्र करने और फ़लस्तीनी समस्या के समाधान की मांगों पर अभी बहुत काम करना बाकी है।

Advertisement

क्या इस संघर्ष में हमारी स्थिति ने मध्य पूर्व के उन देशों के साथ संबंधों में शायद कुछ ठंडक ला दी है, जिनके साथ अतीत में हमारे रिश्ते मधुर रहे हैं? पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हालिया रक्षा समझौता इसका संकेत देता है। इसके अलावा, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच फिर से बना दोस्ताना भी हमारे लिए चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिका को ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और चीन के नज़दीक एक रणनीतिक साझेदार चाहिये...और पाकिस्तान की सीमा इन तीनों से लगती है। वहीं ख़ुफ़िया जानकारी और रसद सहायता प्रदान करने में भी वह उपयोगी है। पाकिस्तान की सभी पक्षों के साथ खेलने की चाह का असर अफ़ग़ानिस्तान के साथ लगती उसकी उत्तरी सीमाओं पर पहले ही पड़ रहा है, जहां झड़पें और हताहतों की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तानी एक ही वक्त चीन और अमेरिका के साथ संबंधों के संतुलन को कैसे साध पाएगा, यह एक कूटनीतिक कौतुक होगा।

यह परिस्थिति हमारी सुरक्षा के लिए सवाल पैदा करती है कि क्या अमेरिका और चीन, पाकिस्तान को लुभाने की खातिर, कश्मीर के बारे उसकी आसक्ति में साथ देंगे? क्या इस क्षेत्र में संघर्ष बड़ी ताकतों को माफिक होगा? दशकों से, हमारी नियंत्रण रेखा सक्रिय रही है, जिस पर पूर्ण युद्ध से लेकर बमबारी और सीमित झड़पों तक, विभिन्न स्तर के टकराव होते आए हैं। हालिया मुठभेड़ ने दोनों पक्षों की एक-दूसरे को पहले की अपेक्षा अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ड्रोन व उपग्रहों की मदद से लैस आधुनिक हवाई शक्ति का उपयोग स्पष्टतया रेंज और क्षमता, दोनों में, वृद्धि-विस्तार दर्शाता है। क्या हम दुश्मन को मात देने की क्षमता प्रदर्शित करने में सफल रहे?

पिछली झड़प के बाद से, बयानबाज़ी तेज़ हो गई और युद्ध के नगाड़े बजते सुनाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम, इस झड़प के परिणाम की धारणा दोनों पक्षों में बहुत अलग रही है; द्वितीय धमकियां और जवाबी धमकियां रोज़ की बात हो गयी - न केवल राजनेता, बल्कि सैन्य अधिकारी भी इस खेल में शामिल हो गए। सशस्त्र बल मूक भागीदार नहीं; अब खुलकर चुनौतियां व धमकियां देने लगे हैं। आए दिन कोई न कोई जनरल या फील्ड मार्शल अपनी बयानबाज़ी में और धार लाता नज़र आता है। हमारा कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वे भी उसी भाषा में बोल रहे हैं। एक-दूसरे के इतिहास और भूगोल को दफनाने की धमकियां नया आयाम है। ठीक इसी वक्त, दोनों मुल्क कुछ देशों की राजधानियों में अपनी स्थिति की पैरवी करने और मजबूत में करने में लगे हैं, ज़्यादा हथियार, ज़्यादा संधियां... हम वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, लंदन आदि में बैठे अपने 'अंकलों' की ओर देखते हैं। जितना ज़्यादा हम पैरवी करने और संबंध बनाने को भागदौड़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा संभावना रहेगी कि हम किसी बहुत बड़े खेल में फंस जाएं और मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाएं।

रूस-यूक्रेन संघर्ष जारी है; नाटो व अमेरिका इसमें सक्रियता से शामिल हैं। चीन ज्यादा शांत रहकर, किंतु शायद अधिक अहम भूमिका निभा रहा है। हम पर रूसी तेल खरीदने के लिए अत्यधिक शुल्क लगाए जा रहे हैं, जबकि नाटो देश खुद वही कर रहे हैं। तब हम अपनी कौन सी स्थिति रखें?

आइए पहले हम अपने गिरेबान में झांकें कि हम कहां जा रहे हैं। जहां हम दूरदराज की महाशक्तियों की मनुहार-प्रशंसा करने में लगे हैं वहीं अपने भीतर भी देखें। हमने अपनी पिछली असफलताओं से कोई सबक नहीं सीखा, और उन्हें दोहराने पर तुले हैं। हमारे सीमावर्ती राज्यों में तनाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। लगभग सभी राज्यों में विकास का अभाव, गरीबी, युवाओं की समस्याओं की उपेक्षा और बेरोजगारी एक समान है। आज का महत्वाकांक्षी युवा पुराने,भ्रष्ट नेताओं की चालबाजियां समझ चुका है। ये मूल मुद्दे देश में तनावों का मुख्य कारण हैं।

यदि हमें देश में शांति-सद्भाव रखना है, तो इन मुद्दों का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। ये हमारी अखंडता व संप्रभुता के लिए खतरा हैं। बांग्लादेश को ही लीजिए, जो आज हमारा शुभचिंतक नहीं। इसके नए नेताओं ने खुलेआम हमारे पूर्वोत्तर में समस्याएं पैदा करने और 'चिकन नेक' का इस्तेमाल इस क्षेत्र को शेष भारत से अलग करने वाले भाषण दिए हैं। पूर्वोत्तर सूबे, खासकर मणिपुर व नगालैंड, बेहद अशांत बने हैं। पिछले कुछ वर्षों से, मणिपुर में सामाजिक दरार गहरा रही है और वह बाकी देश से कटा पड़ा है। लद्दाख काफी समय से पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा है, और चीन के साथ विवाद को देखते हुए इसे और अशांत नहीं होने देना चाहिए। पंजाब शांत जरूर है, लेकिन घटनाओं की जिस श्रृंखला ने किसानों के बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, उससे कट्टरपंथी तत्वों को मौका मिला। हाल में आई भीषण बाढ़ और पश्चिमी देशों से लोगों का निर्वासन भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं। युवाओं के आगे बढ़ने का रास्ता तो दूर, अगर हम बाढ़ का ढंग से प्रबंधन नहीं कर सके, तो कुछ भी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर युवाओं के पास रोज़गार नहीं होगा, तो पंजाब के आपराधिक गिरोह और पश्चिम के गैंगस्टर आपस में मिल जाएंगे और हमारी जड़ों पर चोट करेंगे। राज्य को कहीं से समुद्र तट नहीं लगता, व्यापार के लिए इसके पास कोई खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं ...बल्कि सीमा शत्रुतापूर्ण है। नगण्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क और अधिक अलगाव की ओर ले जाएगा, कोई खास विनिर्माण आधार नहीं और हमारे पास आईटी क्षेत्र का बुनियादी ढांचा नहीं। तब युवा आपराधिक गिरोहों की तोप का चारा नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे?

हम समुदायों के बीच रार पैदा कर आसानी से फायदे का खेल खेल सकते हैं, आपस में तोड़ने के बहाने कई हैं...आक्रमणकारी, मुगल, मंगोल, आर्य- यह एक लंबी सूची है। ऐसे विभाजन लगभग सभी देशों में हैं। यहां,अंग्रेजों से सीखें कि कैसे उन्होंने स्कॉटिश, आयरिश, वेल्श, नॉर्मन, सैक्सन, वाइकिंग आदि समुदायों के साथ उचित रूप से हिस्सा साझा कर रखा है। जिन राष्ट्रों-राज्यों ने मतभेदों पर पार पाते हुए राष्ट्र-निर्माण के मूल सिद्धांतों पर ध्यान दिया, वे सब समृद्ध बने। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के विश्वविद्यालय व स्कूल सदियों से कायम और फलते-फूलते रहे हैं और वहां से पढ़े छात्रों ने ही ऐसे-ऐसे आविष्कार और विचार दिए, जिसने उन्हें आगे बढ़ाया है।

प्रेरणा

झाड़ू दर्शन : एक दिवालीपूर्व आत्मकथा

दिवाली आने को है। शहर के हर घर में झाड़ू की खड़खड़ाहट गूंज रही है। गलियां चमकाई जा रही हैं, दीवारें पोंछी जा रही हैं और हर घर का आदमी या तो झाड़ू खरीदने में व्यस्त है या झाड़ू से भागने में। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। फर्क बस इतना है कि इस बार झाड़ू मेरे लिए कोई साधारण वस्तु नहीं रही, बल्कि जीवन का दार्शनिक प्रतीक बन गई है।

इस कहानी की शुरुआत एक हादसे से हुई, जिसे घर के लोग 'रानी का ब्याह' कहते हैं। रानी कोई राजकुमारी नहीं थी, वह हमारी घरेलू देवी थी—बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, और झाड़ू-बुहारू रानी। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत संतोष था। वह घर की हर गंदगी, हर धूल और हर झंझट को अपनी हथेली पर लेकर बहा देती थी। उसके जाने के बाद जैसे घर से उजाला चला गया। उसकी शादी की विदाई के साथ ही हमारे जीवन की सफाई की गारंटी भी चली गई।

अब जब झाड़ू हमारे हाथ में आई तो पहली बार समझ आया कि घर में इतने कोने आखिर क्यों होते हैं। एक कोना साफ करते तो दूसरा धूल का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता। मकड़ी, कॉकरोच, छिपकली—सब जैसे मुझसे वर्षों का बदला लेने को तैयार बैठे थे। झाड़ू हाथ में लेकर मैं जंग के मैदान में उतरता, पर नतीजा वही—झाड़ू टूटती और पत्नी का रोष फूटता। महंगाई के जमाने में झाड़ू भी सस्ती नहीं रही। झाड़ू टूटने पर पत्नी की आंखें ऐसे फैल जातीं जैसे मैंने कोई राष्ट्रीय अपराध कर दिया हो। और मैं सोचता—हाय रानी! तू यह सब कैसे सह लेती थी?

झाड़ू के प्रति मेरा यह संघर्ष नया नहीं था। बचपन से झाड़ू मेरे जीवन का रहस्यमय पात्र रही है। कहानियों में जादूगरनियां इसी पर उड़ान भरती थीं। जब रात में आंखें खुलतीं, तो लगता कोई अदृश्य बुढ़िया इसी झाड़ू पर बैठकर हमारे आंगन में चक्कर लगा रही है। सुबह देखता, झाड़ू वैसे ही कोने में टिकी है, लेकिन डर अब भी मन में रहता। यही झाड़ू कभी मोहल्ले के झगड़ों में हथियार बनती, तो कभी मां के हाथ में अनुशासन का प्रतीक। जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, झाड़ू का मतलब बदलता गया—कभी भय, कभी आदर, कभी व्यंग्य।

अब सोचता हूं कि झाड़ू दरअसल जीवन का प्रतीक है। जैसे झाड़ू हर कोने की धूल हटाती है, वैसे ही समय हमारे भीतर की धूल हटाता है—पुराने अहंकारों, टूटी इच्छाओं, और छिपे हुए पछतावों की। दिवाली पर जब पूरा देश अपने घरों की सफाई में जुटा होता है, तो मुझे लगता है हमें अपने भीतर की भी सफाई करनी चाहिए। कितनी ही मकड़ियां हैं हमारे मन में—ईर्ष्या, स्वार्थ, क्रोध, और दिखावे की। इन्हें बुहारने के लिए भी एक झाड़ू चाहिए—पर वह झाड़ू बाजार में नहीं मिलती। वह झाड़ू आत्मबोध की होती है, जिसे चलाने के लिए साहस चाहिए।

कभी-कभी मैं सोचता हूं कि अगर देश की राजनीति में भी ऐसी झाड़ू चल जाए तो कितना अच्छा हो। नेताओं के भाषणों, वादों, और घोषणाओं की धूल कितनी मोटी परत बनाकर बैठी है। जो नेता जनता के सामने झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाते हैं, वे असल में केवल कैमरे की सफाई करते हैं, न कि समाज की। असली सफाई तो तब होगी जब कोई अपने भीतर के लालच, झूठ, और दिखावे को बुहारे। लेकिन कौन करेगा? सबको बस फोटो में साफ दिखना है, असलियत चाहे कितनी ही धूल भरी क्यों न हो।

मैं अब झाड़ू को देखकर हंसता नहीं, उसे प्रणाम करता हूं। वह मुझे जीवन की सच्चाई सिखाती है—कि हर चमक के पीछे एक झाड़ू छिपी होती है, और हर उजाले से पहले धूल उड़ती है। जब मैं दरवाजे बंद कर अकेले झाड़ू लगाता हूं, तो लगता है जैसे मैं अपने भीतर की गंदगी भी साफ कर रहा हूं। पत्नी कहती है कि मैं झाड़ू बहुत धीरे लगाता हूं, पर मुझे लगता है कि मैं एक ध्यान कर रहा हूं। हर बुहार के साथ एक पुरानी स्मृति, एक टूटी उम्मीद, एक भूला रिश्ता हट जाता है।

अब तो हाल यह है कि जब भी किसी झाड़ू की खड़खड़ाहट सुनता हूं, मुझे लगता है—कोई और नहीं, स्वयं जीवन मेरे भीतर झाड़ू चला रहा है। रानी भले चली गई, पर उसकी छोड़ी झाड़ू अब मेरा गुरु बन गई है। दिवाली के इस मौसम में, जब लोग लक्ष्मी के स्वागत के लिए सोने-चांदी खरीद रहे हैं, मैं एक नई झाड़ू खरीदने जा रहा हूं। यह झाड़ू मेरे घर की नहीं, मेरे मन की सफाई करेगी। जब मैं झाड़ू चलाऊंगा, तो धूल उठेगी, रोशनी झिलमिलाएगी और भीतर से एक आवाज आएगी—"अब सच में दिवाली हो गई।"

समृद्ध का एहसास कराता है धनतेरस

धनतेरस का त्योहार दीपावली पर्व के प्रारम्भ को दर्शाता करता है। धनतेरस पूजा को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। यह त्योहार लोगों के जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य लाने के लिए माना जाता है और इसलिए इसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर सम्भव न हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चन्द्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में सन्तोष रूपी धन का वास होता है। धनतेरस का दिन धन्वन्तरी त्रयोदशी या धन्वन्तरि जयन्ती भी होती है। धनतेरस को आयुर्वेद के देवता का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी घर लाएं जाते है। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के साथ-साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। पूरे वर्ष में एक मात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। यह पूजा दिन में नहीं की जाती अपितु रात्रि होते समय यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दौरान अपने घर में 13 दीये जलाना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिसमें से सबसे पहले दक्षिण दिशा में यम देवता के लिए और दूसरा धन की देवी मां लक्ष्मी के लिए जलाना चाहिए। इसी तरह दो दीये अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीया तुलसी महारानी के लिए एक दीया घर की छत पर और बाकी दीये घर के अलग-अलग कोने में रख देने चाहिए। माना जाता है कि यह 13 दीये नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से रक्षा करते हैं।

धनतेरस के दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए यमुना स्नान भी किया जाता है अथवा यदि यमुना स्नान सम्भव न हो तो स्नान करते समय यमुना जी का स्मारण मात्र कर लेने से भी यमराज प्रसन्न होते हैं। हिन्दु धर्म की ऐसी मान्यता है कि यमराज और देवी यमुना दोनों ही सूर्य की सन्ताने होने से आपस में भाई-बहिन हैं और दोनों में बड़ा प्रेम है। इसलिए यमराज यमुना का स्नान करके दीपदान करने वालों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते और उन्हें अकाल मृत्यु के दोष से मुक्त कर देते है।

धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा है कि जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। घरों में दीपावली की सजावट भी इसी दिन से प्रारम्भ होती है। इस दिन घरों को लीप-पोतकर, चौक में रंगोली बनाकर सायंकाल के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। धनतेरस को चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ होता है। इस दिन कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, कुआं, बावड़ी, मंदिर आदि स्थानों पर तीन दिन तक दीपक जलाना चाहिए।

धनतेरस के दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता हैं। इस दीप को यमदीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रूई की बत्ती बनाकर, चार बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। चूंकि यह दीपक मृत्यु के नियन्त्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है, अतः दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन तो करें। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु न हो। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है।

धनतेरस को मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा करने के लिए संध्या के समय एक वेदी (पाट्टा) पर रोली से स्वास्तिक बनाइये। उस स्वास्तिक पर एक दीपक रखकर उसे प्रज्वलित करें और उसमें एक छिद्रयुक्त कोड़ी डाल दें। अब इस दीपक के चारों ओर तीन बार गंगा जल छिडकें। दीपक को रोली से तिलक लगाकर अक्षत और मिष्ठान आदि चढाएं। इसके बाद इसमें कुछ दक्षिणा आदि रख दीजिए जिसे बाद में किसी ब्राह्मण को दे देवें। अब दीपक पर कुछ पुष्पादि अर्पण करें। इसके बाद हाथ जोडकर दीपक को प्रणाम करें और परिवार के प्रत्येक सदस्य को तिलक लगाएं। अब इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के दाहिनी और रख दीजिए। यम पूजन करने के बाद अन्त में धनवंतरी पूजा करें।

इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुण्डली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक चार दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा।

राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और उन्होने राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गये और उन्होंने गन्धर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के चार दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे उस वक्त उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। परन्तु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी वक्त उनमें से एक ने यमदेवता से विनती की। हे यमराज क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमदेवता बोले हे दूत अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं सो सुनो।

अभियान

धनतेरस का दीप-विचार : लक्ष्मी आमंत्रण की सच्ची साधना

धनतेरस, दीपावली से दो दिन पहले आने वाला वह शुभ क्षण है जब पूरा देश धन की देवी महालक्ष्मी और आयु व स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरि का स्वागत करता है। यह वह समय है जब बाजार जगमगा उठते हैं, सोने-चांदी की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है, और हर घर में "आज कुछ नया खरीदना है" की धुन बजती है। किंतु इसी उत्साह में लोग कई बार ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जो शुभ के बजाय अशुभ परिणाम दे जाते हैं। धर्म, वास्तु और ग्रह-नक्षत्र की दृष्टि से कुछ वस्तुएं ऐसी मानी गई हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस के दिन लक्ष्मी के आगमन को रोक देती है। इसलिए इस पवित्र अवसर पर थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है।

सबसे पहले बात आती है लोहे की वस्तुओं की। लोहे का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। शनि कठोर अनुशासन, कर्म और न्याय के स्वामी हैं, जबकि लक्ष्मी को कोमलता, सौम्यता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब शनि की कठोरता और लक्ष्मी की कोमलता एक साथ आती है, तो ऊर्जा में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसीलिए इस दिन लोहे के ताले, कैंची, चाकू या बर्तन खरीदना निषेध बताया गया है। लोहे की जगह पीतल, तांबा, चांदी या सोने की वस्तुएं खरीदी जाएं तो वह लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं।

काले रंग की वस्तुएं भी इस दिन वर्जित मानी जाती हैं। काला रंग शनि और राहु की छाया का प्रतीक है। यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और प्रकाश का विरोधी है। धनतेरस का सार ही प्रकाश का आह्वान है — अंधकार से बाहर आना, भीतर के तम को हटाना। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति फैशन के मोह में काले वस्त्र या सजावटी सामान खरीद ले, तो वह अज्ञानवश अंधकार को ही निमंत्रण दे बैठता है। इस दिन लाल, पीले, सुनहरे या सफेद रंग के वस्त्र और वस्तुएं अधिक शुभ फल देती हैं।

धनतेरस पर सिक्के खरीदने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। किंतु ध्यान रहे कि केवल नए सिक्के ही शुभ माने जाते हैं। पुराने या पहले से उपयोग किए गए सिक्कों में किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा बस चुकी होती है। जब उन्हें घर लाया जाता है, तो वह ऊर्जा भी साथ आती है — जो कभी शुभ तो कभी बाधक हो सकती है। इसलिए इस दिन नए लक्ष्मी-गणेश वाले सिक्के या प्रतिमाएं खरीदकर उनका पूजन करना ही सच्चा मंगलकारी आचरण है।

कांच की वस्तुएं भी इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कांच नाजुकता और अस्थिरता का प्रतीक है। धनतेरस का उद्देश्य स्थायित्व और समृद्धि है, अतः कांच की चमक के स्थान पर धातु की दृढ़ता अधिक कल्याणकारी मानी गई है। कांच का टूटना दरिद्रता और कलह का सूचक माना गया है। इसलिए इस दिन धातु के बर्तन, दीपक या आभूषण लेना उत्तम रहता है।

झाड़ू की बात भी विशेष है। कई लोग इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि यह घर की गंदगी और नकारात्मकता को हटाती है। किंतु इसके साथ नियम भी हैं — झाड़ू टूटी हुई, पुरानी या प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसे दिन के उजाले में खरीदा जाए, शाम के अंधेरे में नहीं, अन्यथा माना जाता है कि लक्ष्मी उसी झाड़ू के साथ घर से विदा हो जाती हैं।

और सबसे बड़ी भूल जो लोग कर बैठते हैं — कर्ज लेकर खरीदारी करना। धनतेरस पर ऋण लेना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह वह दिन है जब लक्ष्मी को 'आमंत्रित' किया जाता है, लेकिन कर्ज लेकर की गई खरीदारी से घर में ऋण और बाधा का चक्र आरंभ हो जाता है। इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है और व्यक्ति धीरे-धीरे आर्थिक जाल में फंस सकता है।

धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है। यह आत्म-समृद्धि का उत्सव है — अपने घर, मन और कर्म को स्वच्छ करने का दिन। जब दीपक जलता है, तो वह केवल रोशनी नहीं फैलाता, वह संकेत देता है कि भीतर भी एक ज्योति प्रज्वलित हो। इस दिन की गई शुभ खरीदारी तभी सार्थक होती है जब उसमें श्रद्धा, संयम और कृतज्ञता की भावना हो।

इसलिए इस धनतेरस पर यदि आप वास्तव में मां लक्ष्मी को घर बुलाना चाहते हैं, तो केवल वस्तुएं नहीं, अपने विचार भी उजले करें। लोभ, ईर्ष्या, असत्य और आलस्य जैसे मनोविकारों को बाहर झाड़ें। स्वच्छ मन, पवित्र कर्म और सच्चे भाव ही वह दीपक हैं जिनकी लौ में लक्ष्मी स्वयं अवतरित होती हैं।

धनतेरस की खरीदारी में शुभता तभी टिकेगी जब मन में विनम्रता और भाव में प्रकाश रहेगा। लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां न कोई छल है, न अंधकार। इस दिवाली, सोने की नहीं — सच्चे मन की चमक खरीदिए। तभी घर में दीपक भी जलेगा, और भीतर भी उजाला होगा।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

राज्य मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय

कैबिनेट मंत्रीः

श्री जितेन्द्रभाई सवजीभाई वाघाणी

सीट नंबर : 105, निर्वाचन क्षेत्र : भावनगर (पश्चिम) (भावनगर शहर)
जन्म : 28 जुलाई, 1970, वरतेज
व्यवसाय : कृषि और निर्माण
संसदीय करियर : 13वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। 14वीं गुजरात विधानसभा के दौरान 16 सितंबर 2021 से 09 दिसंबर 2022 तक प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री के रूप में सेवाएं दीं। इसके अलावा, 15वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में गुजरात विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में 20 अप्रैल 2023 से कार्यरत हैं।
शौक : पठन, समाज सेवा, लोक साहित्य, खेल और यात्रा

श्री नरेशभाई मगनभाई पटेल

सीट नंबर : 176, निर्वाचन क्षेत्र : गणदेवी (अ.ज.जा.) (जिला- नवसारी)
जन्म : 1 जून, 1969, मोगरावाड़ी, नवसारी
व्यवसाय : कृषि और व्यापार
संसदीय करियर : 12वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। 14वीं गुजरात विधानसभा में आदिजाति विकास और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और ग्राहक सुरक्षा विभाग के मंत्री के रूप में सेवाएं दीं।
शौक : पठन, लेखन, संगीत और क्रिकेट

श्री अर्जुनभाई देवाभाई मोढवाडिया

सीट नंबर : 83, निर्वाचन क्षेत्र : पोरबंदर (जिला- पोरबंदर)
जन्म : 17 फरवरी, 1957, मोढवाडा, पोरबंदर
व्यवसाय : सामाजिक गतिविधियां और कृषि
संसदीय करियर : 11वीं और 12वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा, उन्होंने अगस्त-सितंबर, 2003 के दौरान श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के एशिया क्षेत्र की दूसरी कॉन्फ्रेंस में गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया।
शौक : पठन, टेनिस, वृक्षारोपण, युवा गतिविधियां और व्यसन निर्मूलन

डॉ. प्रद्युमन गनुभाई वाजा

सीट नंबर : 92, निर्वाचन क्षेत्र : कोडिनार (अ.जा.) (जिला- गिर-सोमनाथ)
जन्म : 18 अगस्त, 1969, कुतियाणा
व्यवसाय : डॉक्टर
संसदीय करियर : 12वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे।
गतिविधियां : ट्रस्टी, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन
शौक : पठन, यात्रा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां

श्री रमणभाई भीखाभाई सोलंकी

सीट नंबर : 109, निर्वाचन क्षेत्र : बोरसद (जिला- आणंद)
जन्म : 28 अप्रैल, 1965, वटादरा, तहसील-खंभात
व्यवसाय : सेवानिवृत्त शिक्षक, कृषि
संसदीय करियर : 15वीं गुजरात विधानसभा में उप मुख्य सचेतक के रूप में 12 दिसंबर, 2022 से कार्यरत रहे
गतिविधियां : वर्ष 2005 से 2010 के दौरान जिला पंचायत में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा, ठाकोर समाज के मंत्री के रूप में भी सेवाएं दीं।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) :

श्री ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल

सीट नंबर : 154, निर्वाचन क्षेत्र : अंकलेश्वर (जिला- भरूच)
जन्म : 25 जून, 1965, मु.पो. कुडादरा, तहसील-हांसोट, भरूच
व्यवसाय : कृषि
संसदीय करियर : 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। वे सहकारिता, खेल, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग में 2 मार्च, 2009 से 1 फरवरी, 2011 के दौरान संसदीय सचिव रहे। इसके अलावा, उन्होंने 2 फरवरी, 2011 से 25 दिसंबर, 2012 के दौरान सहकारिता, खेल, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग के राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं। उन्होंने 7 अगस्त, 2016 से 25 दिसंबर, 2017 के दौरान सहकारिता विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभाला है तथा दिसंबर, 2017 से सितंबर, 2021 के दौरान सहकारिता, खेल, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग का स्वतंत्र प्रभार और परिवहन विभाग के राज्य मंत्री के रूप में सेवादायित्व संभाला। उन्होंने विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति, पंचायती राज समिति और आश्वासन समिति के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
शौक : पठन, व्यायाम, यात्रा, खेल, समाज सेवा और वृक्षारोपण

डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील

सीट नंबर : 141, निर्वाचन क्षेत्र : वडोदरा (अ.जा.) (वडोदरा शहर)
जन्म : 25 मार्च, 1975, वडोदरा
व्यवसाय : सुपरवाइजर और शिक्षक, ब्राइट डे स्कूल
संसदीय करियर : 13वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहीं। उन्होंने सितंबर-2021 से दिसंबर-2022 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं।
शौक : पठन

श्रीमती रीवाबा रवीन्द्रसिंह जाडेजा

सीट नंबर : 78, निर्वाचन क्षेत्र : जामनगर (उत्तर) (जामनगर जिला)
जन्म : 5 सितंबर, 1990, राजकोट
व्यवसाय : समाज सेवा
गतिविधियां : संस्थापक व मैनेजिंग ट्रस्टी, मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट। कन्या केळवणी, महिला सशक्तिकरण आदि से जुड़ी गतिविधियां तथा तत्संबंधी केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को समाज तक पहुँचाने के कार्य से जुड़ी हुई हैं।
शौक : पठन, यात्रा-पर्यटन तथा समाज सेवा

राज्य मंत्री :

श्री कांतिलाल शिवलाल अमृतिया

सीट नंबर : 65, निर्वाचन क्षेत्र : मोरबी (जिला- मोरबी)
जन्म : 8 मार्च, 1962, जेतपुर, तहसील और जिला-मोरबी
व्यवसाय : कृषि, उद्योग और शिक्षा
संसदीय करियर : 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं गुजरात विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे।
शौक : पठन, समाज सेवा, यात्रा, खेल, क्रिकेट, टेनिस और तैराकी

श्री रमेशभाई भूराभाई कटारा

सीट नंबर : 129, निर्वाचन क्षेत्र : फतेपुरा (अ.ज.जा.) (जिला- दाहोद)
जन्म : 4 मई, 1975, हिंगला
व्यवसाय : कृषि
संसदीय करियर : 13वीं और 14वीं गुजरात विधानसभा में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा, उन्होंने सितंबर-2021 से दिसंबर-2022 के दौरान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
गतिविधियां : सदस्य, जिला पंचायत-दाहोद
शौक : पठन और समाज सेवा

श्रीमती दर्शनाबेन मुकेशभाई वाघेला

सीट नंबर : 56, निर्वाचन क्षेत्र : असारवा विधानसभा (अहमदाबाद शहर)
जन्म : 5 सितंबर, 1972, अहमदाबाद
व्यवसाय : पूर्व शाला आचार्य
गतिविधियां : अहमदाबाद महानगर पालिका में दो कार्यकाल तक पार्षद रहीं। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2010 से 2013 के दौरान अहमदाबाद महानगर पालिका में उप महापौर के रूप में सेवाएं दी हैं। वे सफाई कामदार निगम की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और हाल में वाल्मीकि फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं।
शौक : पठन, वक्तव्य

श्री कौशिकभाई कांतिभाई वेकरिया

सीट नंबर : 95, निर्वाचन क्षेत्र : अमरेली विधानसभा (जिला- अमरेली)
जन्म : 9 जून 1986, मोजे खीचा, तहसील धारी, जि. अमरेली
व्यवसाय : कृषि, व्यवसाय (श्री द्रोणेश्वर पेट्रोलियम)
संसदीय कॅरियर : 15वीं गुजरात विधानसभा में मुख्य उप सचेतक के रूप में दि. 12 दिसंबर 2022 से कार्यरत थे।
गतिविधियां : निदेशक, गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड, दि. 29/03/2016 से कार्यरत। पूर्व निदेशक, खेतीबाड़ी उत्पाद बाजार समिति, अमरेली
शौक : राजपुरुषों की जीवनगाथा तथा विश्व के राजनीतिक इतिहास का पठन, सामाजिक गतिविधियां, जनसंपर्क, यात्रा-पर्यटन, सिंह दर्शन

श्री प्रवीणकुमार गोरधनजी माली

सीट नंबर : 13, निर्वाचन क्षेत्र : डीसा (जिला- बनासकांठा)
जन्म : 8 मार्च 1985, डीसा
व्यवसाय : कृषि एवं व्यापार
गतिविधियां : संयोजक, प्रदेश भाजपा प्रलेखन विभाग। ट्रस्टी, महात्मा ज्योतिबा फुले एजुकेशन ट्रस्ट, डीसा
शौक : पठन, साइकलिंग, वॉलीबॉल

डॉ. जयरामभाई चेमाभाई गामित

सीट नंबर : 172, निर्वाचन क्षेत्र : नीझर (अजजा) (जिला- तापी)
जन्म : 1 जून 1975, कटारावाण, तहसील- उच्छल (तापी)
व्यवसाय : कृषि एवं पशुपालन
गतिविधियां : अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, तापी जिला
शौक : लेखन, पठन, सांस्कृतिक कार्यक्रम

श्री त्रिकमभाई बीजलभाई छांगा

सीट नंबर : 4, निर्वाचन क्षेत्र : अंजार (जिला- कच्छ)
जन्म : 1 जून, 1962, रतनाल, अंजार, कच्छ
व्यवसाय : सेवानिवृत्त आचार्य
गतिविधियां : वर्ष 2000 से 2010 तक अंजार तहसील पंचायत के सदस्य के रूप में सेवाएं दीं और फिर 2010 से 2015 तक कच्छ जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दीं।
शौक : पठन

श्री कमलेशभाई रमेशभाई पटेल

सीट नंबर : 113, निर्वाचन क्षेत्र : पेटलाद (जिला- आणंद)
जन्म : 12 अप्रैल 1970, संतोकपुरा, बोरसद
व्यवसाय : कृषि एवं नौकरी (आचार्य, शाहपुर हाईस्कूल)
गतिविधियां : उन्होंने पेटलाद तहसील भाजपा अध्यक्ष, चौद गाम केळवणी उत्तेजक ट्रस्ट के सचिव तथा पेटलाद एजुकेशन ट्रस्ट के सदस्य के रूप में सेवाएं दीं।
शौक : पठन एवं समाज सेवा

श्री संजयसिंह विजयसिंह महिडा

सीट नंबर : 118, निर्वाचन क्षेत्र : महुधा (जिला- खेड़ा)
जन्म : 20 अक्टूबर 1979, त्राणजा, मातर
व्यवसाय : कृषि एवं व्यापार
गतिविधियां : अध्यक्ष, नडियाद तहसील पंचायत। पूर्व अध्यक्ष-कारोबारी समिति-तहसील पंचायत, तहसील संगठन महासचिव (2020 तक), सचिव-महिडा मेलड़ी माताजी मंदिर सेवा समाज ट्रस्ट, पूर्व कोषाध्यक्ष-जिला युवा मोर्चा, शिवाजी फाउंडेशन में सेवा गतिविधियों में सक्रिय।
शौक : पठन तथा संगीत

श्री पूनमचंद धनाभाई बरंडा

सीट नंबर : 30, निर्वाचन क्षेत्र : भिलोडा (अ.ज.जा.) (जिला- अरवल्ली)
जन्म : 1 जून, 1959, वांकाटिंबा
व्यवसाय : कृषि
गतिविधियां : प्रदेश भाजपा आदिजाति मोर्चे के महासचिव के रूप में सेवाएं दीं।
शौक : पठन तथा खेल

श्री स्वरूपजी सरदारजी ठाकोर

सीट नंबर : 7, निर्वाचन क्षेत्र : वाव (जिला- बनासकांठा)
जन्म : 1 जून, 1979, बैयक
व्यवसाय : कृषि, व्यापार
गतिविधियां : उपाध्यक्ष, गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना
शौक : पठन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में शामिल उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा नवनियुक्त मंत्रियों में 5 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 12 राज्य मंत्री शामिल

▸▸ राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने महात्मा मंदिर में आयोजित गौरवशाली समारोह में मंत्रियों को दिलाई शपथ

▸▸ कैबिनेट मंत्री श्री कनुभाई देसाई, श्री ऋषिकेशभाई पटेल, श्री कुंवरजीभाई बावळिया तथा राज्य मंत्री श्री परषोत्तमभाई सोलंकी को वर्तमान मंत्रिपरिषद में बरकरार रखा गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में नए शामिल किए गए उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल के समक्ष उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री हर्ष संघवी तथा राज्य मंत्रिपरिषद के 5 कैबिनेट मंत्रियों, 3 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 12 मनोनीत राज्य मंत्रियों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली।

कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री जितेन्द्रभाई वाघाणी, श्री नरेशभाई पटेल, श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युम्नभाई वाजा और श्री रमणभाई सोलंकी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में श्री ईश्वरसिंह पटेल, श्री प्रफुल्लभाई पानसेरिया और श्रीमती मनीषा वकील ने शपथ ग्रहण की।

वहीं, राज्य मंत्री के रूप में श्री कांतिलाल अमृतिया, श्री रमेशभाई कटारा, श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, श्री कौशिकभाई वेकरिया, श्री प्रवीणकुमार माळी, डॉ. जयरामभाई गामित, श्री त्रिकमभाई छांगा, श्री कमलेशभाई पटेल, श्री संजयसिंह महीड़ा, श्री पी.सी. बरंडा, श्री स्वरूपजी ठाकोर और श्रीमती रीवाबा जाडेजा ने राज्यपाल के समक्ष शपथ ली। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों सर्वश्री कनुभाई देसाई, ऋषिकेशभाई पटेल और कुंवरजीभाई बावळिया तथा राज्य मंत्री श्री परषोत्तमभाई सोलंकी को इस नई मंत्रिपरिषद में बरकरार रखा गया है।

इस शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्वश्री मनसुख मांडविया, सी.आर. पाटिल, सांसद एवं विधायक, संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ अग्रणी, साधु-संतों और समाज के विभिन्न वर्गों के अग्रणियों सहित अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं विशाल संख्या में शुभचिंतक उपस्थित रहे। मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया।

गुजरात से औद्योगिक नमक की पहली रेल खेप कश्मीर पहुँची

(जीएनएस)। कश्मीर घाटी में माल परिवहन के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। 1,350 टन औद्योगिक नमक की पहली रेल खेप गुजरात के अहमदाबाद मंडल के खाराघोड़ा (KOD) स्टेशन से जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग (ANT) स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुँची है।

स्थानः खाराघोड़ा गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले में स्थित एक प्रसिद्ध नमक उत्पादन क्षेत्र है, जो लिटिल रण ऑफ कच्छ की सीमा पर बसा हुआ है।

शुद्धताः खाराघोड़ा का नमक अपनी उच्च गुणवत्ता और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उत्पादित कुछ प्रकार के नमक में 98% से अधिक सोडियम क्लोराइड (NaCl) होता है। इस क्षेत्र की रिफ़ाइनरियाँ औद्योगिक और खाद्य दोनों श्रेणियों का नमक तैयार करती हैं।

प्रयोगः इस खेप का उपयोग चमड़ा उद्योग, साबुन निर्माण तथा ईंट भट्ठों में किया जाएगा।

यह उपलब्धि कश्मीर में रेल नेटवर्क के माध्यम से ग़ैर-पारंपरिक माल ढुलाई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे परिवहन समय और लागत में कमी आने के साथ-साथ सड़क परिवहन पर निर्भरता भी घटेगी।

यह रेल रेक लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय कर खाराघोड़ा से अनंतनाग पहुँची।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा,यात्रियों से जुड़ने के लिए "अमृत संवाद" का आयोजन बदलाव के लिए बातचीत, सेवा के लिए प्रतिबद्धता - जन संवाद से जन विकास

(जीएनएस)। पहली तस्वीर में मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर अमृत संवाद के दौरान यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अमृत काल के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त पंच प्राण के मार्गदर्शक सिद्धांतों से प्रेरित होकर पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को मुंबई सेंट्रल स्टेशन के कॉनकोर्स एरिया में एक गतिशील "अमृत संवाद" का आयोजन किया गया। विशेष अभियान 5.0 के तहत आयोजित इस पहल का उद्देश्य सामूहिक भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे अधिकारियों और यात्रियों के बीच सीधे जुड़ाव को बढ़ावा देना था।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम का नेतृत्व मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह ने किया, जिन्होंने अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ एक खुले प्रश्नोत्तर सत्र में यात्रियों से सीधे बातचीत की। इस संवाद में यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जन सुरक्षा, स्टेशन सुविधाओं, डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ प्रीमियम स्लीपर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बारे में प्रश्न पूछे और सुझाव साझा किए।

मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह ने प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक उत्तर दिया और यात्रियों को यात्री सुविधाओं में वृद्धि, सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने और आधुनिक, तकनीक-संचालित यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयासों का आश्वासन दिया। उन्होंने यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने, ज़िम्मेदार यात्रा आदतें अपनाने और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सकारात्मक योगदान देकर रेलवे के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

अमृत संवाद पहल का उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच सहभागिता को सशक्त बनाते हुए ऐसा संवाद मंच तैयार करना है, जहां जनसुझावों को ठोस नीतिगत एवं विकासात्मक कार्यों में रूपांतरित किया जा सके। यह पहल अमृत काल और पंच प्राण के संकल्पों से प्रेरित होकर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आंबलियासन–वीजापुर रेलखंड में 120 किमी की स्पीड से ट्रेन का हुआ संचालन,42 किमी की दूरी 25 मिनट में की पूरी, औसत गति 101 किमी से अधिक की आई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन–वीजापुर रेलखंड (42.32 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण रेलवे संरक्षा आयुक्त (CRS), वेस्टर्न सर्कल श्री ई. श्रीनिवास द्वारा 16 एवं 17 अक्टूबर, 2025 को किया गया। अंतिम संरक्षा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। इस रेलखंड को मई 2022 में 415.37 करोड़ की लागत से मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब यह खंड यात्रियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित एवं सुचारू रेल संचालन हेतु लगभग तैयार है। रेल सुरक्षा आयुक्त (पश्चिम सर्कल) द्वारा किया गया वैधानिक निरीक्षण कमीशनिंग से पहले एक आवश्यक कदम है। निरीक्षण टीम ने स्टेशन सुविधाओं, ट्रैक ज्योमेट्री, घुमाव, पुलों और रोड अंडर ब्रिज (RUBs) की विस्तृत जांच की। इसमें 02 मेजर ब्रिज, 51 माइनर ब्रिज और 45 नए रोड अंडर ब्रिज (RUBs) शामिल हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे लाइन को लेवल क्रॉसिंग के समीप फेंसिंग द्वारा सुरक्षित किया गया है, तथा इस खंड पर कुल 04 लेवल क्रॉसिंग्स हैं। 17 अक्टूबर, 2025 को विभिन्न स्थानों पर विस्तृत निरीक्षण किया गया। कुकरवाडा से वीजापुर तक लगभग 15 किमी का ट्रॉली निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात आंबलियासन–वीजापुर रेलखंड (42.32 किमी) पर 120 किमी/घंटे की स्पीड से गति परीक्षण किया गया। इस दौरान श्री ई. श्रीनिवास, रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम रेलवे, श्री वेद प्रकाश मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद; श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कुकरवाडा स्टेशन पर प्लेटफार्म की ऊँचाई, कॉपिंग और एंड पाथवे की जांच की गई। RUB संख्या 65 B में ऊँचाई, गेज और जल निकासी की व्यवस्था देखी गई, साथ ही MDD (Maximum Dry Density) टेस्ट, बैंक स्लोप और सेस की चौड़ाई की भी जांच की गई।

इसी प्रकार, गेरिता–कोलवाड़ा में प्लेटफार्म की माप और एंड पाथवे की जाँच की गई। RUB संख्या 79B की ऊँचाई, गेज, जल निकासी और पैदल मार्ग की व्यवस्था देखी गई। विजापुर स्टेशन पर ट्रैक के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत निरीक्षण किया गया। प्लेटफार्म की कॉपिंग, ऊँचाई एंड पाथवे की जांच की गई। विजापुर स्टेशन में सबवे का निरीक्षण किया गया, साथ ही यात्रियों की सुविधाओं की भी जाँच की गई।

इस गेज परिवर्तन परियोजना से यात्रियों और क्षेत्र को कई लाभ प्राप्त होंगे। मालगाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित होगा और इस खंड के चालू होने से विजापुर क्षेत्र से कॉटन, गेहूँ, आलू एवं टोबेको, तेल उत्पाद इत्यादि की आपूर्ति देशभर में अधिक सुगमता से हो सकेगी, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी। अभी तक सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता था, वह अब रेल मार्ग से शीघ्र भेजा जा सकेगा। इससे स्थानीय व्यापारियों को लाभ होगा तथा रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी। यात्रियों को बेहतर और तेज़ रेल संपर्क उपलब्ध होगा, विशेष रूप से उत्तर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत संरचनाओं और आधुनिक सुरक्षा उपायों के साथ यात्रा अब अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।

ऑपरेशन जीवन रक्षा

अपनी जान जोखिम में डालकर कांस्टेबल श्री रमेश जाधवने बचाई एक बच्चे की जान

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के गोधरा के रेल सुरक्षा बल में कार्यरत कांस्टेबल श्री रमेश जाधव ने अत्यंत साहस, त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर असावधानीवश ट्रेन से गिरे एक 3 वर्षीय बालक की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 16.10.2025 को ट्रेन नं 19038 बरौनी - बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस के कोच सं S5 में श्री संतोष यादव अपनी पत्नी एवं 03 वर्षीय पुत्र के साथ मुजफ्फरपुर से वापी यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान कानसुधी–गोधरा रेलखंड पर, ट्रेन के गोधरा यार्ड में प्रवेश से पहले, बालक अपनी माता के साथ शौचालय जाते समय असावधानीवश दरवाजे के पास से फिसलकर दूसरी रेल लाइन पर नीचे गिर गया। बालक के गिरते ही यात्रियों द्वारा तत्काल चेन खींचकर ट्रेन रोकी गई। उसी दौरान ड्यूटी पर तैनात गोधरा में कार्यरत कांस्टेबल श्री रमेश जाधव ने घटना स्थल पर बालक को देखा। उसी समय उस रेल लाइन पर ट्रेन नं 12951 मुंबई - नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्री रमेश जाधव ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना अत्यंत साहस, त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए तेज गति से लाइन पर दौड़ लगाई और आने वाली ट्रेन के पहले बालक तक पहुँचकर उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया।

श्री रमेश जाधव ने बालक की तत्परता से जान बचाने के बाद उसे उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया। यात्री ने अपने पुत्र के शरीर पर कोई चोट ना आने की पुष्टि की तथा अपनी यात्रा जारी रखी। घटना के पश्चात कोच में उपस्थित सभी यात्रियों एवं परिजनोंने कांस्टेबल श्री रमेश जाधव के साहसिक कार्य की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

पश्चिम रेलवे ऐसे कर्तव्यनिष्ठ रेलकर्मी पर गर्व करती है, जो लोगों के लिए मानवता की मिसाल हैं।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मण्डल

ई-निविदा सूचना संख्या : **Sr.DEE/ADI/30(25-26)** दिनांक : **16.10.2025**

सिलींग फेन के बॉल बेरिंग के प्रतिस्थापन और रिवाइंडींग के संबंध में बिजली कार्य

निविदा सं. **EL-50-1-ADI-T-37-2025-26**

कार्य का नाम: अहमदाबाद मण्डल के सभी SSE/ELECT. के क्षेत्राधिकार आधिन सिलींग फेन के बॉल बेरिंग के प्रतिस्थापन और रिवाइंडींग के संबंध में बिजली कार्य ।

अनुमानित लागत: ₹ 16,59,560/- | **बयाना राशि:** ₹ 33,200/-

निविदा जमा करने एवं खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक: 11/11/2025 को 15:00 बजे उसके बाद नहिं एवं दिनांक: 11/11/2025 को 15:30 बजे निविदा खोली जायेगी ।

कार्यालय का पता एवं वेबसाईट विवरण: वरिष्ठ मण्डल बिजली अभियंता, म.रे.प्र. कार्यालय (प.रे.), चामुंडा पुल के पास, जी.सी.एस. अस्पताल के सामने, नरोडा रोड़, अमदुपुरा, अहमदाबाद-382345 **वेब साईट का पता:** www.ireps.gov.in

ADI-185

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: x.com/WesternRly

भारत अगले दशक में खर्च करेगा 7.4 अरब डॉलर, लड़ाकू विमानों के इंजन निर्माण में बढ़ाएगा स्वदेशी क्षमता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत आने वाले दस वर्षों में अपने रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश लड़ाकू विमानों के इंजन निर्माण और खरीद पर लगभग 7.4 अरब डॉलर (करीब 6.54 लाख करोड़ रुपये) खर्च करेगा। यह जानकारी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अधीन गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टैब्लिशमेंट (जीटीआरई) के निदेशक एस. वी. रमण मूर्ति ने शुक्रवार को दी। मूर्ति के अनुसार, भारत को वर्ष 2035 तक लगभग 1,100 नए इंजनों की आवश्यकता होगी, जो देश के विभिन्न लड़ाकू विमान कार्यक्रमों — जैसे तेजस मार्क-2, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर (TEDBF) और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) — में इस्तेमाल किए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण में अग्रणी बनाना है और विदेशी निर्भरता को न्यूनतम करना है।

भारत की महत्वाकांक्षी 'कावेरी इंजन परियोजना', जिसे कभी देश के स्वदेशी तेजस विमान को शक्ति देने के लिए शुरू किया गया था, लंबे समय तक तकनीकी जटिलताओं के कारण ठप रही। हालांकि अब इस परियोजना में नई जान फूंकने की कोशिशें हो रही हैं। मूर्ति के मुताबिक, कावेरी इंजन का एक संशोधित संस्करण अब भारत के स्वदेशी मानवरहित लड़ाकू विमान (UCAV) के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यह भारत के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि यह तकनीक उसे पश्चिमी देशों पर निर्भरता से काफी हद तक मुक्त कर सकती है।

देश फिलहाल अपने पहले पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर विमान, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के लिए एक अत्याधुनिक इंजन विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। मूर्ति ने बताया कि इस इंजन के सह-विकास के लिए तीन बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों — फ्रांस की सैफरान, ब्रिटेन की रॉल्स-रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक — ने रुचि दिखाई है।

यह इंजन न केवल भारत के स्टेल्थ विमानों को ताकत देगा, बल्कि इसे भविष्य में नौसेना के विमान बेड़े में भी उपयोग किया जा सकता है। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है और इसे भारत की रक्षा उत्पादन यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है।

निजी क्षेत्र को पहली बार मिलेगी भागीदारी

इस बार भारत सरकार ने फैसला किया है कि लड़ाकू विमान इंजन निर्माण की इस विशाल परियोजना में निजी कंपनियों को भी बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि अब तक अधिकांश विमान निर्माण परियोजनाएं केवल सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) तक सीमित रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि HAL पर बोझ कम हो और साथ ही देश में रक्षा विनिर्माण की क्षमता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ाई जाएं।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का कहना है कि यह निवेश भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकता है। आज भी भारत अपने अधिकांश फाइटर इंजनों के लिए विदेशों पर निर्भर है। ऐसे में घरेलू इंजन निर्माण से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि तकनीकी ज्ञान और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

मूर्ति ने कहा, "हमारा लक्ष्य केवल आयात घटाना नहीं है, बल्कि भारत को इंजन निर्यातक राष्ट्र बनाना है। आने वाले वर्षों में हमारे वैज्ञानिक और औद्योगिक साझेदार इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाएंगे।"

कुल मिलाकर, भारत का यह कदम न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई परिभाषा देगा, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी तकनीकी क्षमता और रणनीतिक ताकत को भी सशक्त करेगा।

महाभिड़ंत: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नए राजनीतिक चार्टर के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को अंतरिम सरकार के नए राजनीतिक चार्टर के विरोध में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भयंकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारी राजधानी में संसद भवन के सामने जमा हुए और चार्टर के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे। थोड़ी ही देर बाद, यह विरोध हिंसक रूप ले गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। जब यह तरीका काम नहीं आया तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अंतरिम सरकार का नया चार्टर उनकी चिंताओं और मांगों को नजरअंदाज करता है। प्रदर्शनकारी, जो पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके थे, इस बार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली कार्यवाहक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने कहा कि चार्टर में उन लोगों के लिए कोई कानूनी सुरक्षा या पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है, जो 2024 में हुए प्रदर्शनों में घायल हुए थे।

सुबह ही प्रदर्शनकारी संसद भवन के मुख्य द्वार पर चढ़ गए और परिसर में कथित तौर पर घुसकर मंच के सामने इकट्ठा हो गए। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अतिथियों के लिए आरक्षित कुर्सियों पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। इस दौरान उन्होंने कम से कम दो पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और अस्थायी स्वागत कक्ष, नियंत्रण कक्ष और फर्नीचर में आग लगा दी।

अंतरिम सरकार द्वारा गठित आयोग और राजनीतिक दलों के बीच लंबी बातचीत के बाद जुलाई चार्टर का मसौदा तैयार किया गया था। हालांकि, नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) ने स्पष्ट किया है कि वह इस चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय सहमति का दिखावा कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। वहीं, हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चर्चा का हिस्सा नहीं थी क्योंकि सरकार ने उसके नेताओं पर मुकदमा चलने तक उनकी गतिविधियों को रोक दिया था और अधिकांश नेता जेल में हैं या फरार हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह हिंसक प्रदर्शन बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। चार्टर में शामिल 80 से अधिक सिफारिशों के बावजूद, विभिन्न दलों के बीच असहमति और जनता की नाराजगी ने राजधानी को हिंसक प्रदर्शनों के लिए संवेदनशील बना दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर विरोध जारी रहा तो सुरक्षा बलों को और कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है।

इस प्रदर्शन ने एक बार फिर बांग्लादेश में राजनीतिक असंतोष और जनता के गुस्से को उजागर किया है। सरकार और विपक्षी दलों के बीच संवाद और समाधान के अभाव ने स्थिति को ज्वलंत बना दिया है, और देश में भविष्य की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बेंगलुरु के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी छात्र गिरफ्तार, कैंपस सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

(जीएनएस)। बेंगलुरु। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट माने जाने वाले बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक भयावह घटना ने पूरे शैक्षणिक जगत को झकझोर दिया है। बसवंगुड़ी स्थित इस कॉलेज में सातवें सेमेस्टर की एक छात्रा के साथ उसके ही जूनियर छात्र ने कैंपस के अंदर दुष्कर्म किया। यह घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है, लेकिन पीड़िता ने मानसिक आघात और भय के कारण तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने 15 अक्टूबर को अपने माता-पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 21 वर्षीय जीवन गौड़ा के रूप में हुई है, जो उसी कॉलेज का छात्र है। घटना की सूचना मिलते ही बसवंगुड़ी थाने की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कॉलेज प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज, कैंपस सुरक्षा रिकॉर्ड और छात्रों की उपस्थिति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं ताकि पूरे मामले की सटीक जांच की जा सके।

जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर को कॉलेज में एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के बहाने आरोपी ने छात्रा को कैंपस के एक निर्जन हिस्से में बुलाया। वहां उसने जबरदस्ती की और धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देगा। डर और शर्म के कारण छात्रा ने कुछ दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन लगातार बढ़ते मानसिक तनाव ने उसे तोड़ दिया। अंततः उसने अपने माता-पिता को सब कुछ बताया, जिन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, कॉलेज परिसर में अपराध होने के कारण, कैंपस सुरक्षा की भूमिका और लापरवाही की भी जांच की जा रही है। बीएमएस कॉलेज प्रशासन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि वे पुलिस जांच में हर संभव सहयोग करेंगे। कॉलेज प्रबंधन ने यह भी घोषणा की है कि वह अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करेगा, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और छात्र-छात्राओं के बीच सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

यह घटना उस समय सामने आई है जब देशभर में कॉलेज परिसरों में बढ़ते यौन अपराधों पर लगातार बहस हो रही है। समाजशास्त्रियों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और संवेदनशीलता की कमी का गंभीर उदाहरण है।

महिला संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि कॉलेज परिसरों में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू किए जाएं और ऐसे मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाए।

पीड़िता का बयान अदालत के समक्ष दर्ज किया गया है और फिलहाल उसे चिकित्सकीय देखभाल और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं।

बेंगलुरु जैसे महानगर में, जो देश की तकनीकी राजधानी के रूप में जाना जाता है, इस तरह की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान छात्रों के लिए वास्तव में सुरक्षित हैं? यह मामला समाज को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर गया है कि तकनीकी तरक्की के बीच भी अगर बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, तो विकास का अर्थ अधूरा रह जाता है।

सबरीमाला गोल्ड चोरी केस में मुख्य आरोपी उन्निकृष्णन पोट्टी गिरफ्तार, SIT की रिमांड 30 अक्तूबर तक

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। केरल के पथनमथिट्टा में स्थित प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। स्थानीय रणनी कोर्ट ने शुक्रवार को सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले के मुख्य आरोपी उन्निकृष्णन पोट्टी को 30 अक्तूबर तक एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) की रिमांड पर भेज दिया। आरोपी को गुरुवार-शुक्रवार की रात 2:30 बजे हिरासत में लिया गया था और शुक्रवार सुबह 14 घंटे से अधिक पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट ले जाते समय आरोपी ने मीडिया से कहा कि उसे किसी ने फंसाया है और जो भी दोषी हैं, वे कानून के सामने आएंगे। वहीं, कोर्ट के बाहर जमा भीड़ में किसी ने पोट्टी पर जूता फेंक दिया, जिसे पुलिस ने तुरंत रोक लिया और आरोपी को सुरक्षित कोर्ट ले जाया गया।

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में जांच में पाया था कि द्वारपालक मूर्तियों पर चढ़ाए गए सोने की प्लेट्स का वजन जब ट्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (TDB) ने उन्निकृष्णन पोट्टी को सौंपा था, तब 42.8 किलो था, लेकिन जब यह चेन्नई स्थित कंपनी स्मार्ट क्रिएशंस को भेजा गया तो केवल 38.2 किलो पहुंचा। इस अंतर को देखते हुए हाईकोर्ट ने TDB की विजिलेंस विंग से शुरुआती जांच कराने का निर्देश दिया। जांच में पोट्टी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने एसआईटी गठित करने का फैसला लिया। एसआईटी अब मामले की गहन जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि सोने की चोरी में पोट्टी का कितना हाथ था और अन्य लोग इसमें शामिल थे या नहीं।

पुलिस और विजिलेंस टीम के शुरुआती राउंड की जांच में पता चला कि सोने की चोरी मंगलवार और बुधवार की रातों में हुई थी, और इसमें मंदिर के कर्मचारियों और बाहरी दलों की मिलीभगत हो सकती है।

एसआईटी की रिमांड में आरोपी से पूछताछ का लक्ष्य चोरी की पूरी प्रक्रिया, अन्य आरोपी और सोने की असली लोकेशन का पता लगाना है। अधिकारियों ने कहा कि रिमांड के दौरान सभी कड़ियों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया जाएगा और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त गिरफ्तारी भी हो सकती है।

इस बीच, मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा कड़े कर दी है और गर्भग्रह समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर असली सोने की प्लेट्स और आभूषणों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने यह भी कहा कि अब से कोई भी सामान बिना रिकॉर्ड और निगरानी के मंदिर से बाहर नहीं जाएगा।

सबरीमाला सोने की चोरी का मामला राज्य में बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। धार्मिक स्थल से जुड़े होने और उच्च मूल्य के सोने से जुड़े होने के कारण, पुलिस और एसआईटी की जांच को राज्यभर में बड़े ध्यान और निगरानी के साथ देखा जा रहा है। यह मामला धार्मिक स्थल की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए भी एक चेतावनी है कि मंदिरों और सार्वजनिक संपत्ति की निगरानी में लापरवाही नहीं हो सकती।

पश्चिम रेलवे द्वारा ऊर्जा संरक्षण के बेहतर उपायों की पहल

(जीएनएस)। आज के दौर में जहाँ ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, रेलवे द्वारा अपने नेटवर्क में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के बिजली विभाग द्वारा बिजली की खपत कम करने, परिचालन दक्षता में सुधार लाने और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाने के उद्देश्य से ऊर्जा-बचत पहल शुरू की गई है। ये प्रयास एक हरित भविष्य के निर्माण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत पश्चिम रेलवे द्वारा कई प्रभावशाली ऊर्जा संरक्षण अभियान शुरू किए गए हैं। ये प्रयास भारतीय रेल की पर्यावरण संरक्षण और परिचालन दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। इस पहल के अंतर्गत, मुंबई सेंट्रल मंडल के स्टेशनों और सेवा भवनों पर लगभग 12,500 ऊर्जा-कुशल ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (BLDC) पंखे लगाए गए हैं। बीएलडीसी पंखे पारंपरिक सीलिंग पंखों की अपेक्षा लगभग 40% कम बिजली का उपयोग करते हैं, साथ ही ये अधिक शांत, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले होते हैं। इसके अलावा, मंडल द्वारा स्टेशनों, कार्यालयों और सेवा क्षेत्रों में 1,48,700 से अधिक एलईडी फिक्स्चर लगाकर ऊर्जा-कुशल एलईडी प्रकाश व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन हासिल किया गया है। इस पहल से बिजली की खपत और रखरखाव की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता बनाए रखने के लिए, दादर, बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, भायंदर, सूरत, उधना, नंदुरबार और वापी सहित प्रमुख स्टेशनों पर 10 प्राकृतिक वाटर कूलर लगाए गए हैं। ये कूलर बिना कंप्रेसर के काम करते हैं और इनकी शीतलन क्षमता 45 लीटर प्रति घंटा है। ये 150 लीटर तक पानी संग्रहित कर सकते हैं। ये कूलर न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करते हुए 23C से 27C के बीच तापमान बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, मुंबई सेंट्रल मंडल में एयर-कंडीशनिंग सिस्टम को और अधिक कुशलता से अनुकूलित करने के लिए 1,200 से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी सेंसर लगाए गए हैं। ये स्मार्ट सेंसर मानवीय उपस्थिति का पता लगाते हैं और स्वचालित रूप से एयर-कंडीशनिंग को समायोजित करते हैं, जिससे खाली कमरों में अनावश्यक ऊर्जा की खपत कम होती है। इन निरंतर प्रयासों के माध्यम से, पश्चिम रेलवे नवीन और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एक मजबूत उदाहरण स्थापित कर रही है, जो एक हरित और अधिक ऊर्जा-कुशल भविष्य के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

आंध्र और कर्नाटक के आईटी मंत्रियों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग, निवेश को लेकर बढ़ा राजनीतिक तापमान

(जीएनएस)। अमरावती। दक्षिण भारत के दो पड़ोसी राज्यों — आंध्र प्रदेश और कर्नाटक — के बीच एक बार फिर डिजिटल मैदान में राजनीतिक तकरार छिड़ गई है। इस बार बहस का केंद्र बना है निवेश, आईटी सेक्टर और राज्यों की आर्थिक स्थिति। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश और कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, जिसने दोनों राज्यों के समर्थकों को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है।

दरअसल, आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने हाल ही में एक्स पर लिखा— "कहते हैं आंध्र का खाना मसालेदार होता है, लगता है हमारे निवेश भी वैसे ही हैं। कुछ पड़ोसी पहले से ही इसकी गर्मी महसूस कर रहे हैं।" इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। लोकेश ने यह दावा भी किया कि भारत के सबसे युवा राज्य आंध्र प्रदेश को हाल के वर्षों में सबसे अधिक विदेशी निवेश मिला है। उन्होंने विशाखापत्तनम में गूगल के 15 अरब डॉलर के एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सौदा हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ और यह आंध्र प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। लोकेश के इस बयान पर कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने लिखा— "निवेश केवल घोषणाओं से नहीं आते, बल्कि बुनियादी ढांचे, नीति और भरोसे से आते हैं। कुछ लोग आंकड़ों से खेलते हैं, जबकि कुछ लोग असली नवाचार को प्राथमिकता देते हैं।" खड़गे ने व्यंग्य करते हुए यह भी कहा कि "कागज पर दिखाए गए अरबों डॉलर के निवेश तब तक वास्तविक नहीं होते जब तक वे धरातल पर उतर न जाएं।" इस तकरार के बाद दोनों राज्यों के समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। आंध्र के लोगों ने लोकेश का समर्थन करते हुए कहा कि विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति तेजी से आईटी उद्योग के नए केंद्र बन रहे हैं। वहीं कर्नाटक के यूजर्स ने खड़गे के पक्ष में यह तर्क दिया कि बेंगलुरु अब भी देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कैपिटल है, जहां विश्व की 400 से अधिक फॉर्च्यून कंपनियों के अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों राज्यों के बीच यह प्रतिस्पर्धा तकनीकी रूप से लाभदायक भी है, क्योंकि इससे निवेशकों को बेहतर विकल्प मिलते हैं और दक्षिण भारत का आईटी इकोसिस्टम मजबूत होता है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी चेताया कि इस प्रतिस्पर्धा को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय सहयोग में बदलना अधिक उपयोगी होगा। दिलचस्प बात यह है कि गूगल का 15 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है और केंद्र सरकार की मंजूरी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे दिग्गजों के साथ नई साझेदारियों की घोषणा कर चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, नारा लोकेश और प्रियांक खड़गे दोनों युवा नेता हैं और अपने-अपने राज्यों में तकनीकी विकास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं।

अहमदाबाद मंडल ने फेस्टिवल सीजन के दौरान व्यापक भीड़ प्रबंधन हेतु उठाये अहम कदम

- यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा
- सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद मंडल ने की व्यापक तैयारी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा आगामी दीवाली एवं छठ पूजा त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही में अपेक्षित भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित, सुचारू और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करने हेतु व्यापक भीड़ प्रबंधन एवं यात्री सुविधा उपाय किए गए हैं। इसके अंतर्गत अहमदाबाद, असारवा, साबरमती एवं गांधीधाम स्टेशनों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। अहमदाबाद, असारवा और साबरमती स्टेशनों पर राउंड-द-क्लॉक (24x7) अधिकारियों की निगरानी में व्यापक प्रबंध किए गए है ताकि प्रत्येक स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। अहमदाबाद स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु सरसपुर साइड 3230 वर्ग फूट तथा प्लेटफॉर्म नं. 01 की ओर 8072 वर्ग फूट के यात्री होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, प्रकाश, पंखे, शौचालय एवं सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

साबरमती स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग में टिकट काउंटर और 4-5 हजार यात्रियों के बैठने की सुविधा की गई है। प्रवेश एवं निकास द्वारों को पृथक रखा गया है ताकि यातायात प्रवाह सुचारू रहे। इसके अतिरिक्त, 15 से 28 अक्टूबर 2025 तक मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है, जिससे किसी आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो सके।

भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुविधा देने हेतु अतिरिक्त टिकट बुकिंग काउंटर शुरू किए गए हैं। कतार नियमन, यात्री सहायता एवं सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टिकट जांच कर्मचारी एवं RPF कर्मी भी लगाए गए हैं। प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए स्टेशनों पर कवर्ड होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिससे ट्रेन के प्रस्थान तक यात्री आराम से प्रतीक्षा कर सकें।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा ड्यूटी के दौरान वॉकी-टॉकी एवं बॉडी-वॉर्न कैमरा का उपयोग कर निर्बाध डिजिटल संचार बनाए रखा जा रहा है। इसके साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अहमदाबाद मंडल कार्यालय में 'वार रूम' (War Room) स्थापित किया गया है, जहां से वास्तविक समय पर सभी स्टेशनों से समन्वय करते हुए स्थितियों की निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यात्रियों के लाभ हेतु ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि त्योहारी सीजन में भी यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध बनी रहे। इन उपायों से यात्रियों को लंबी कतारों, अनावश्यक भीड़भाड़ और असुविधा से राहत मिलेगी, साथ ही स्टेशन परिसर में सुरक्षा और स्वच्छता का स्तर भी बेहतर रहेगा। पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे स्टेशन परिसर में निर्धारित होल्डिंग एरिया का उपयोग करें और सुरक्षा कर्मियों एवं रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि सभी यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव सुखद और सुरक्षित बन सके।

"स्वच्छता पखवाड़ा – 2025" के अंतर्गत भावनगर मंडल में विविध कार्यक्रमों का सफल आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल पर "स्वच्छता पखवाड़ा – 2025" के अंतर्गत विभिन्न स्वच्छता एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान का शुभारंभ 01 अक्टूबर 2025 को प्रभात फेरी एवं स्वच्छता शपथ के साथ हुआ। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में रेलकर्मी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं वरिष्ठ मंडल याँत्रिक इन्जीनियर श्री संतोष कुमार मिश्रा की देखरेख में चलाए गए अभियान के दौरान प्रत्येक दिन को एक विशिष्ट थीम के अंतर्गत मनाया गया, जिनमें प्रमुख रूप से — स्वच्छता शपथ दिवस, स्वच्छता जागरूकता दिवस, स्वच्छ भारत दिवस, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ ट्रैक, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ कार्यस्थल, स्वच्छ आवासीय परिसर, स्वच्छ आहार, स्वच्छ पानी, स्वच्छ प्रसाधन, सिंगल यूज प्लास्टिक निषेध एवं स्वच्छता रैली शामिल थे।

महात्मा गांधी जयंती एवं स्वच्छ भारत दिवस (02 अक्टूबर 2025) के अवसर पर वृक्षारोपण, निरीक्षण एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने विभिन्न स्थलों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही, चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता 12 बच्चों एवं स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

"स्वच्छ रेलगाड़ी" थीम के अंतर्गत पोरबंदर, भावनगर एवं वेरावल कोचिंग डिपो में ट्रेनों की गहन यांत्रिक सफाई की गई। साथ ही, स्टेशनों पर यात्रियों के बीच स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। "स्वच्छ आहार" दिवस के अवसर पर मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा भावनगर टर्मिनस, जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर, जेतलसर, बोटाद, सोनगढ़, धोला एवं धोलका स्टेशनों पर खाद्य स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। पेंट्री कार विक्रेताओं एवं स्टॉल संचालकों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई तथा उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छ आहार के महत्व से अवगत कराया गया।

अभियान के दौरान मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर गहन सफाई अभियान चलाया गया। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं एवं कार्यालयों की संपूर्ण सफाई कर कर्मचारियों एवं यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। "स्वच्छ पटरी" कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों द्वारा रेलवे ट्रैकों की सफाई की गई।

इसके अतिरिक्त, "वेस्ट टू आर्ट", श्रमदान, रैलियों एवं वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों के माध्यम से रेलकर्मियों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। यात्रियों से स्वच्छता के संबंध में फीडबैक लिया गया तथा भविष्य की योजनाओं हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने 17 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार) को मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिती में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और "स्वच्छता पखवाड़ा – 2025" अभियान के अंतर्गत किये गये क्रियाकलापों की जानकारी दी एवं कहा कि भावनगर मंडल ने इस पखवाड़े को जन-अभियान का स्वरूप देते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया की 1 से 15 अक्टूबर तक चले इस अभियान के दौरान हमारे मंडल के 66 रेलवे स्टेशनों को कवर किया गया। लगभग 925 कर्मचारियों और नागरिकों ने स्वच्छता शपथ ली और 12400 वर्गमीटर क्षेत्र की सफाई की गई। 160 मीटर नालियों की सफाई, 9 स्थानों पर फ्यूमीगेशन, और 9 एंटी-लिटरिंग ड्राइव्स के माध्यम से हमने स्वच्छता को जन-जागरूकता से जोड़ा। "स्वच्छ परिसर" के तहत 39 कार्यालयों की सफाई एवं सौंदर्यीकरण किया गया, जबकि 36 किलोमीटर ट्रैक की सफाई और 2.3 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का निस्तारण हुआ। "स्वच्छ नीर" अभियान में 15 जलस्थलों और 10 पानी के बूथों की सफाई एवं जल गुणवत्ता की जांच की गई। भावनगर मंडल के सभी स्टेशनों पर अब साफ-सुथरे प्लेटफॉर्म, सुधरी हुई जल व शौचालय सुविधाएँ, और स्वच्छ वातावरण यात्रियों को एक नया अनुभव दे रहे हैं। भावनगर मंडल ने इस अवसर पर यह संकल्प लिया कि "स्वच्छता ही सेवा" के आदर्शों को आत्मसात करते हुए रेलवे परिसरों को स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ बनाए रखने हेतु अपने प्रयास निरंतर जारी रखेगा।